



किस्ती भी तरह के विज्ञापन एवं समाचार के लिए संपर्क करें मो०: 9891706853



नोएडा उत्तर प्रदेश,दिल्ली एनसीआर, हरियाणा,पंजाब बिहार,मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, झारखण्ड असम से प्रसारित

पेपर लीक पर संसद में चर्चा को तैयार सरकार, राहुल के आरोपों पर जेपी नड्डा का पलटवार

नई दिल्ली। केन्द्रीय मंत्री एवं राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने पेपर लीक के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि केंद्र सरकार इस विषय पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और विपक्ष इस गंभीर मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी ने संसद में 150 से अधिक पेपर लीक मामलों का उल्लेख किया, जबकि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन शासित राज्यों में भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार हर तथ्य को सदन के सामने रखेगी और "दूध का दूध, पानी का पानी" करेगी।

उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसे संवेदनशील विषय पर राजनीतिक लाभ लेने की बजाय छात्रों के हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। नड्डा ने विपक्ष को इस मुद्दे पर संसद में सार्थक और तथ्यपरक चर्चा के लिए खुला आमंत्रण भी दिया।

मुनाफे वाली BPCL घाटे में गली गई, पेट्रोल-डीजल सस्ते में बेचे पर भारी नुकसान

सरकारी तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 3,962.13 करोड़ रुपये का भारी भरकम घाटा हुआ है. पिछले 15 तिमाहियों में यह कंपनी का पहला तिमाही घाटा है. यह ऑक्-इंडा इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि पिछले साल ठीक इसी तिमाही में कंपनी ने 3,333.97 करोड़ रुपये का तगड़ा मुनाफा कमाया था. इस भारी नुकसान के पीछे सबसे बड़ी वजह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चा तेल (क्रूड ऑयल) का अचानक बहुत महंगा होना है. दरअसल, 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला किया था, जिसके बाद ईरान ने भी पलटवार किया. पश्चिम एशिया में भड़की इस जंग के कारण ग्लोबल मार्केट में सप्लाई बिगड़ी और कच्चे तेल की कीमतों में 50 फीसदी से ज्यादा का जबरदस्त उछाल आ गया.

गिरिराज सिंह बोले— "जिनके वस्त्र काले हैं, उनके मन भी उतने ही काले हैं"; विपक्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अडिग नीट-यूजी विवाद पर संसद में तीखा गतिरोध, भाजपा का विपक्ष पर कथर प्रहार

समाज जागरण
नई दिल्ली। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) के कथित प्रश्नपत्र लीक प्रकरण को लेकर संसद के मानसून सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव और तेज हो गया है। विपक्ष द्वारा काले वस्त्र धारण कर विरोध प्रदर्शन किए जाने पर भारतीय जनता पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि "जिनके वस्त्र काले हैं, उनके मन भी उतने ही काले हैं।" उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नीट-यूजी प्रकरण पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है, किंतु विपक्ष जानबूझकर सदन की कार्यवाही बाधित कर



रहा है। उनके अनुसार विपक्ष छात्रों के हितों से जुड़े इस गंभीर विषय का राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास कर रहा है। गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार ने सदन में चर्चा कराने का प्रस्ताव रखा था, परंतु विपक्ष ने उसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने

आरोप लगाया कि कांग्रेस सहित विपक्षी दल संसद की कार्यवाही सुचारु रूप से चलने नहीं देना चाहते। केन्द्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि संसद राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर गंभीर और रचनात्मक विमर्श का सर्वोच्च

मंच है। उनका कहना था कि विपक्ष राजनीतिक स्वार्थ और सत्ता की लालसा में सदन की गरिमा को प्रभावित कर रहा है। वहीं केन्द्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि नीट-यूजी प्रश्नपत्र लीक की घटना किसी भी दृष्टि से स्वीकार्य नहीं है तथा केंद्र सरकार इसकी निष्पक्ष एवं गहन जांच करा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि केन्द्रीय शिक्षा

मंत्रि धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा इस समस्या का समाधान नहीं है। उधर विपक्षी सांसद काले वस्त्र पहनकर संसद पहुंचे और नीट-यूजी प्रश्नपत्र लीक प्रकरण तथा दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन किया। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग दोहराते

हुए कहा कि जवाबदेही तय किए बिना चर्चा का कोई औचित्य नहीं है। केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजिजू ने पुनः स्पष्ट किया कि सरकार नीट-यूजी प्रकरण पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि चर्चा का समय और स्वरूप सभी राजनीतिक दलों से परामर्श के बाद निर्धारित किया जाएगा।

बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा पर सरकार सख्त, आईटी नियमों में कड़े प्रावधान

समाज जागरण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नियम और सख्त कर दिए हैं। केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने लोकसभा में बताया कि बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएसएम) और अन्य गैर-कानूनी कंटेंट पर सोशल मीडिया कंपनियों को त्वरित कार्रवाई करनी होगी। संशोधित आईटी नियमों के तहत अदालत या सक्षम प्राधिकारी के आदेश पर तीन घंटे के भीतर गैर-कानूनी सामग्री हटाना अनिवार्य होगा,



जबकि संवेदनशील शिकायतों पर दो घंटे के भीतर कार्रवाई करनी होगी। सरकार ने एआई और डीपफेक सामग्री पर भी कड़ी निगरानी के लिए नए प्रावधान लागू किए हैं तथा प्लेटफॉर्म को ऐसे कंटेंट पर स्पष्ट लेबल और ट्रेस किए जा सकने वाले मेटाडेटा रखने के निर्देश दिए हैं।

अनुराग जैन बने नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईएसएस अधिकारी अनुराग जैन को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया है। वह 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएसएस) अधिकारी हैं। नियुक्ति से पहले वह मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। अनुराग जैन प्रशासनिक और नीति निर्माण के क्षेत्र में लंबे



अनुभव रखते हैं। उनकी नियुक्ति को नीति आयोग की कार्यप्रणाली को और गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। केंद्र सरकार ने उनकी नियुक्ति संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं।

नालों की सफाई, जलनिकासी, बाढ़ प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारियों की समीक्षा, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

जलमयव पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं, जवाबदेही तय कर होगी कड़ी कार्रवाई: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

समाज जागरण
गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा है कि प्रदेश के शहरों में जलभराव की समस्या किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नालों और नालियों की समयबद्ध सफाई, पंपिंग स्टेशनों का प्रभावी संचालन तथा जलनिकासी की समुचित व्यवस्था हर हाल में सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि जलभराव रोकने में किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।



बुधवार को एनेक्सी भवन सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने जिले के विकास कार्यों, बाढ़ प्रबंधन, जलनिकासी व्यवस्था तथा स्वच्छता अभियान की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मानसून के दौरान कहीं भी जलभराव की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय

रहते पूरी कर ली जाएं। मुख्यमंत्री ने सभी नालों और नालियों की नियमित सफाई कराने तथा उन्हें अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रभावी रोक लगाने पर जोर देते हुए कहा कि प्लास्टिक के कारण नालियां जाम होती

हैं और जलभराव की समस्या बढ़ती है। उन्होंने नाला निर्माण एवं मरम्मत संबंधी प्रस्ताव समय पर तैयार कर निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने राप्ती कॉम्प्लेक्स, गोरख एंक्लेव, विजय चौराहा और धर्मशाला क्षेत्र में जलभराव की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि नालों की सफाई के बाद उन्हें व्यवस्थित ढंग से ढका जाए तथा नगर निगम के सभी पंप पूरी क्षमता से संचालित किए जाएं। साथ ही नागरिकों को नालियों में कूड़ा न डालने के लिए जागरूक करने और नियमित स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रत्येक वार्ड, मलिन बस्तियों और खाली पड़े भूखंडों की नियमित सफाई सुनिश्चित करने तथा कूड़ा निस्तारण की प्रभावी व्यवस्था विकसित करने पर बल दिया। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वच्छता अभियान को नियमित गतिविधि बनाने और इसमें जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक भवनों में भी स्वच्छता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया।

उन्होंने शहरी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स को व्यवस्थित करने, सभी स्ट्रीट लाइटों की क्रियाशील रखने तथा सीसीटीवी

कैमरों को अद्यतन स्थिति में बनाए रखने के निर्देश दिए। इसके अलावा बेसहारा गोवंश को सड़कों से हटाने और आवारा कुत्तों के लिए डॉग शेल्टर विकसित करने की आवश्यकता भी बताई। स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश दिए कि जिला अस्पताल सहित सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर एंटी स्नेक वेनम तथा एंटी रैबीज वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे, ताकि किसी भी आपात स्थिति में मरीजों को तत्काल उपचार मिल सके। बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने तटबंधों की नियमित निगरानी, बाढ़ चौकियों को सक्रिय रखने तथा राहत शिविरों में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने बाढ़ संभावित क्षेत्रों में संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए विशेष सतर्कता बरतने और क्षतिग्रस्त सड़कों की समयबद्ध मरम्मत सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। (इनपुट: आईएनएस)

विश्व में चौथे स्थान पर भारत, वर्ष 2030 के लक्ष्य को लेकर सरकार ने तेज की तैयारियां

भारत पवन ऊर्जा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर स्थापित क्षमता 57,443 मेगावाट हुई, एक वर्ष में 106 अरब यूनिट विद्युत उत्पादन

समाज जागरण
नई दिल्ली। भारत स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। देश में पवन ऊर्जा (विंड एनर्जी) की स्थापित क्षमता बढ़कर 57,443 मेगावाट हो गई है। वहीं, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान पवन ऊर्जा परियोजनाओं से 106 अरब यूनिट विद्युत का उत्पादन दर्ज किया गया। यह जानकारी केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में दी।

एनर्जी कार्रिसल (जीडब्ल्यूईसी) की वर्ष 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, 31 दिसंबर 2025 तक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के मामले में भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश बन चुका है। **हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल** राज्य मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के लिए व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना के अंतर्गत नई विद्युत प्रसारण लाइनों और उपकेंद्रों का निर्माण किया जा रहा है, ताकि पवन एवं सौर ऊर्जा का निर्बाध प्रसारण सुनिश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, 30 जून 2025 तक चालू हुई सौर एवं पवन ऊर्जा



परियोजनाओं को अंतरराष्ट्रीय विद्युत प्रसारण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्क में छूट प्रदान की गई है। इसके बाद शुरू होने वाली परियोजनाओं के लिए चरणबद्ध शुल्क व्यवस्था लागू की गई है।

वर्ष 2030 के लक्ष्य के अनुरूप तैयार हो रहा आधारभूत ढांचा

सरकार ने वर्ष 2030 तक निर्धारित नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए देशभर में विद्युत प्रसारण अवसंरचना के

विस्तार की व्यापक योजना तैयार की है। साथ ही इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को स्वचालित मार्ग (ऑटोमैटिक रूट) के माध्यम से अनुमति प्रदान की गई है।

आरपीओ और आरसीओ का पालन होगा अनिवार्य

सरकार ने वर्ष 2029-30 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व (आरपीओ) तथा नवीकरणीय ऊर्जा उपभोग दायित्व (आरसीओ) के लक्ष्य भी निर्धारित किए हैं। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत आने वाले सभी निर्धारित उपभोक्ताओं के लिए इनका पालन अनिवार्य होगा।

राम मंदिर के नए उएड की नियुक्ति तक 5 संत संभालेंगे संचालन, ट्रस्ट ने बनाई धार्मिक समिति

चढ़ावा प्रकरण पर एसआईटी रिपोर्ट का इंतजार, एसबीआई की कार्यप्रणाली पर ट्रस्ट ने जताई नाराजगी

समाज जागरण
अयोध्या। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की मंगलवार को हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की नियुक्ति होने तक मंदिर का संचालन पांच संतों की धार्मिक समिति की देखरेख में होगा। ट्रस्ट ने बताया कि नए सीईओ के चयन में लगभग एक माह का समय लग सकता है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी की अध्यक्षता में गठित धार्मिक समिति में स्वामी रामानंद दास, महंत राजकुमार दास, स्वामी विश्वप्रसन्न तीर्थ, स्वामी कमलनयन दास, स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती और स्वामी दिनेंद्रदास को शामिल किया गया है। बैठक में चढ़ावा गणना में कथित अनियमितताओं को लेकर एसआईटी जांच की प्रगति की समीक्षा की गई। ट्रस्ट ने कहा कि



मामले में एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। ट्रस्ट ने मंदिर परिसर और चढ़ावा गणना कक्ष में लगे सीसीटीवी कैमरों की निगरानी व्यवस्था पर संतोष व्यक्त किया। साथ ही चढ़ावे में प्राप्त सोना-चांदी की मात्रा और शुद्धता की जांच के लिए आरबीआई की

टकसाल (मिंट) के साथ वर्तमान व्यवस्था जारी रखने का निर्णय लिया गया। बैठक में चढ़ावे की गणना से जुड़े कार्य में एसबीआई की लापरवाही पर भी न्यासियों ने नाराजगी जताई और संबंधित प्रक्रियाओं व व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के निर्देश दिए।

आढ़तियों के चंगुल में ग्राहक-किसान, सरकार लाचार

संजय सक्सेना,लखनऊ,

भारतीय कृषि व्यवस्था की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि खेत की मिट्टी से उपज उगाने वाला किसान और रसोई घर का बजट संभालने वाला आम ग्राहक, दोनों एक ही चक्रव्यूह के दो अलग-अलग शिकार हैं। किसान दिन-रात पसीना बहाकर फसल तैयार करता है, लेकिन जब वह बाजार पहुंचता है तो उसकी जेब खाली रह जाती है। दूसरी तरफ, जब वही ग्राहक बाजार में सक्जियां या अनाज खरीदने जाता है, तो आसमान छूती महंगाई उसकी कमर तोड़ देती है। इस पूरी व्यवस्था के बीच एक ऐसा वर्ग पनप रहा है, जो बिना किसी शारीरिक मेहनत के पूरी मंडी प्रणाली पर अपना नियंत्रण जमाए बैठा है ये हैं बिचौलिए यानी 'आढ़ती'। खेत से लेकर ग्राहक की थाली तक के सफर में जो मुनाफा किसान के घर पहुंचना चाहिए था और जो राहत ग्राहक को मिलनी चाहिए थी, वह सब इन आढ़तियों की तिजोरियों में बंद हो रहा है। आज स्थिति यह बन चुकी है कि आढ़तियों के तय किए रेट पर ही किसान बेचने और ग्राहक खरीदने के लिए मजबूर हैं, और सरकार का तंत्र इस पूरे खेल में पूरी तरह मूकदर्शक बना नजर आता है। आंकड़ों पर नजर डालें तो इस शोषण की भयानक तस्वीर साफ दिखने लगती है। भारत में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएसओ) के आंकड़े बताते हैं कि देश में एक कृषि परिवार की औसत मासिक आय मात्र 10,218 रुपये के करीब है। इस मामूली सी रकम में किसान को अपनी खाद, बीज, डीजल, मजदूरी और परिवार के भरण-पोषण का खर्च चलाना पड़ता है। इसके ठीक विपरीत, रिजर्व बैंक और विभिन्न शोध संस्थानों की रिपोर्ट दर्शाती है कि किसान को उपज के अंतिम बाजार मूल्य (यानी जो दाम ग्राहक चुकाता है) का महज 25 से 35 प्रतिशत हिस्सा ही किसान की जेब तक पहुंच पाता है। उदाहरण के लिए, यदि बाजार में टमाटर या प्याज 80 रुपये प्रति किलो बिक रहा है, तो खेत पर किसान को इसका मुश्किल से 12 से 15 रुपये प्रति किलो ही मिलता है। बाकी का लगभग 65 से 75 प्रतिशत हिस्सा बिचौलियों, आढ़तियों, परिवहन और मंडी के विभिन्न स्तरों पर बंट जाता है। यह आंकड़ा साबित करता है कि असली पसीना बहाने वाले को मामूलात्र की मजदूरी मिल रही है, जबकि बीच की कड़ी मुनाफा कूट रही है।

आढ़तियों का यह नेटवर्क इतना मजबूत और संगठित है कि वे मंडी में प्रवेश करते ही किसान की बेबसी का फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। कृषि उपज मंडी समितियों (एपीएमसी) का गठन मूल रूप से इसलिए किया गया था ताकि किसानों को शोषण से बचाया जा सके और उन्हें पारदर्शी तरीके से अपनी फसल का सही दाम मिले। लेकिन समय के साथ ये मंडियां आढ़तियों के एकाधिकार का केंद्र बन गईं। आढ़ती ही यह तय करते हैं कि किसान की उपज की बोली किस दाम से शुरू होगी और किस भाव पर उसे खरीदा जाएगा। किसान के पास न तो अपनी फसल को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए पर्याप्त शीत गृह (कोल्ड स्टोरेज) हैं और न ही उसके पास इतना धैर्य होता है कि वह दाम बढ़ने का इंतजार करे, क्योंकि उसे अगली फसल के लिए कर्ज चुकाना होता है। आढ़तियों को किसान की इस लाचारी का पूरा अहसास होता है। वे एकजुट होकर कृत्रिम रूप से दाम गिरा देते हैं, जिससे किसान औनै-पौनै दामों में अपनी उपज बेचने पर मजबूर हो जाता है।दूसरी ओर, जब यही माल मंडी से बाहर निकलकर खुदरा बाजार की ओर बढ़ता है, तो आढ़तियों का दूसरा खेल शुरू होता है। वे बाजार में आपूर्ति को नियंत्रित करके और अपने पास माल का भंडारण करके खुदरा कीमतों को कृत्रिम रूप से बढ़ा देते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के आंकड़ों के अनुसार, खाद्य मुद्रास्फीति का सीधा असर आम नागरिक की जेब पर पड़ता है। एक औसत भारतीय परिवार अपनी कुल आय का लगभग 40 से 45 प्रतिशत हिस्सा केवल भोजन पर खर्च करता है। जब आढ़तियों और शोकर व्यापारियों के गठजोड़ के कारण सब्जियों और खाद्यान्न के दाम बढ़ते हैं, तो ग्राहक का पूरा मासिक बजट बिगड़ जाता है। ग्राहक मजबूरी में महंगे दामों पर सामान खरीदता है, यह सोचकर कि शायद इसका फायदा किसान को मिल रहा होगा, जबकि हकीकत में किसान पहले ही अपनी फसल कीड़ियों के भाव बेचकर खाली हाथ घर लौट चुका होता है।

इस पूरी व्यवस्था में सरकार और उसके प्रशासनिक ढांचे की भूमिका सबसे ज्यादा निराशाजनक रही है। कागजों पर तो किसान हितैषी कई योजनाएँ हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के दावे हैं और आवश्यक वस्तु अधिनियम जैसे कानून मौजूद हैं, लेकिन धरातल पर आढ़तियों पर किसी का नियंत्रण नहीं है। आज तक शायद ही ऐसा कोई उदाहरण देखने को मिला हो, जब किसी बड़े आढ़ती या गठजोड़ पर जमाखोरी या कीमतों में हेरफेर के लिए कोई कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई हो। जब भी महंगाई बढ़ती है, तो सरकारें थोड़े समय के लिए छापेमारी का नाटक करती हैं या आयात-निर्यात नीतियों में बदलाव करके इतिश्री कर लेती हैं, लेकिन आढ़तियों के इस मजबूत ढांचे पर कोई स्थायी जांच कमेटी या सख्त दंडात्मक कार्रवाई कभी नहीं देखने को मिलती। इसका मुख्य कारण आढ़तियों का राजनीतिक रूप से बेहद प्रभावशाली होना है। स्थानीय राजनीति से लेकर राज्य स्तर के नेताओं तक आढ़तियों का एक गहरा आर्थिक-राजनीतिक गठजोड़ काम करता है, जिसके कारण कानून के हाथ इन तक पहुंचते-पहुंचते बौने साबित हो जाते हैं।विश्व बैंक और नीति आयोग के कई अध्ययन भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि भारत में कृषि विपणन में सुधार न होने का सबसे बड़ा कारण मंडी का यह बंद ढांचा है। देश में लगभग 86 प्रतिशत छोटे और सीमांत किसान हैं, जिनके पास एक या दो हेक्टेयर से कम जमीन है। ये छोटे किसान अपनी थोड़ी सी उपज लेकर दूर के बड़े बाजारों में नहीं जा सकते, इसलिए वे अपने नजदीकी आढ़ती पर ही पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं। आढ़ती केवल व्यापारी नहीं होते, बल्कि वे इन किसानों को खाद-बीज के लिए अनौपचारिक रूप से कर्ज भी देते हैं। इस कर्ज के जाल में फंसा किसान अपनी फसल किसी अन्य को बेचने की स्थिति में ही नहीं रहता। यह आदतों और मजबूरियों का ऐसा टुप्पड़ बन चुका है, जिससे किसान चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाता। यद्यपि हम वैश्विक तुलना करें तो विकसित देशों में किसान की उपज का लगभग 60 से 70 प्रतिशत हिस्सा सीधे किसान तक पहुंचता है, क्योंकि वहां 'खेत से थाली तक' का सीधा संपर्क या तो सहकारिता के माध्यम से है या फिर पारदर्शी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए। भारत में 'ई-नाम' जैसी डिजिटल मंडी योजनाओं की शुरुआत जरूर की गई है, ताकि किसान देश की किसी भी मंडी में अपना माल बेच सके, लेकिन तकनीकी साक्षरता की कमी, इंटरनेट की सुस्त व्यवस्था और आढ़तियों के जमीनी दबदबे के कारण यह व्यवस्था भी अब तक आढ़तियों के तिलस्म को पूरी तरह तोड़ने में असफल रही है।परिणामस्वरूप, किसान लगातार कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है और देश में हर साल हजारों किसान आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या जैसे कदम उठाने पर मजबूर होते हैं। राष्ट्रीय अपघथ रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़े आज भी कृषि क्षेत्र में बढ़ती आर्थिक विषमता और मानसिक तनाव की दर्दनाक गवाही देते हैं। वहीं दूसरी तरफ, शहर का आम ग्राहक अपनी सीमित आय में कटौती करके महंगाई का डंक सहने को विवश है। इन दोनों के आंसुओं के बीच, मंडियों के शेड के नीचे बैठा आढ़ती वर्ग बिना किसी उत्पादन जोखिम के, बिना किसी प्राकृतिक आपदा के खतरे के, हर सीजन में करोड़ों का कारोबार कर रहा है। यह बेहद गंभीर प्रश्न है कि आखिर कब तक देश का अन्नदाता और देश का उपभोक्ता इस शोषणकारी व्यवस्था के चंगुल में फंसेकर पिसते रहेंगे? जब तक आढ़तियों और बिचौलियों को इस एकाधिकारवादी व्यवस्था पर कड़ा प्रहार नहीं किया जाएगा, जब तक उनकी ममनानी कीमतों और जमाखोरी पर निष्पक्ष जांच बिठाकर कड़ी सजा का प्रावधान नहीं होगा, तब तक न तो किसान को उसकी मेहनत का वाजिब हक मिलेगा और न ही आम ग्राहक को महंगाई से राहत मिल पाएगी।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में भारतीय मूल का वैश्विक नेतृत्व

महेन्द्र तिवारी

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आज मानव इतिहास की सबसे परिवर्तनकारी तकनीकों में गिनी जा रही है। जिस प्रकार औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन प्रणाली को बदला, इंटरनेट ने संचार और सूचना के स्वरूप को परिवर्तित किया, उसी प्रकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता आने वाले दशकों में अर्थव्यवस्था, शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा और सामाजिक जीवन को गहराई से प्रभावित करने वाली है। इसी कारण दुनिया के विकसित देश केवल एआई तकनीक विकसित करने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उसके सुरक्षित, जिम्मेदार और नैतिक उपयोग के लिए प्रभावी नीतियां भी बना रहे हैं। ऐसे समय में ब्रिटेन द्वारा भारतीय मूल के कनिष्क नारायण को देश का पहला सर्गीत और कैबिनेट स्तर का कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंत्री नियुक्त करना केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाला कदम माना जा रहा है। यह नियुक्ति तकनीकी नेतृत्व, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और भारतीय प्रतिभा की अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता का भी महत्वपूर्ण प्रतीक बन गई है।

कनिष्क नारायण का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था। जब वे लगभग बारह वर्ष के थे, तब उनका परिवार ब्रिटेन के वेल्स चला गया। प्रारंभिक जीवन आर्थिक चुनौतियों से भरा रहा, लेकिन शिक्षा के प्रति समर्पण और प्रतिभा के बल पर उन्होंने आगे बढ़ते हुए ईटन कॉलेज, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और बाद में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। यह यात्रा केवल व्यक्तिगत सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह दर्शाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी शिक्षा और अवसर व्यक्ति को वैश्विक नेतृत्व तक पहुंचा सकते हैं।

राजनीति में आने से पहले कनिष्क नारायण ने ब्रिटिश सरकार की सखिल सेवा में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। उन्होंने कैबिनेट ऑफिस तथा पर्यावरण विभाग में नीतिगत कार्य किए और बाद में निजी क्षेत्र में भी रणनीतिक एवं आर्थिक विषयों पर अनुभव प्राप्त किया। इस विविध अनुभव ने उन्हें प्रशासन, सार्वजनिक नीति, तकनीकी परिवर्तन और आर्थिक विकास के बीच संबंधों को गहराई से समझने का अवसर दिया। यही कारण है कि उन्हें केवल एक राजनेता नहीं बल्कि नीति निर्माण और तकनीकी प्रशासन की समझ रखने वाले नेता के रूप में देखा जाता है।

साल 2024 के आम चुनाव में उन्होंने वेल ऑफ ग्लैमरगन निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की और वेल्स के पहले जातीय अल्पसंख्यक सांसद बने। इसके बाद उन्हें विज्ञान, नवाचार और प्रौद्योगिकी विभाग में एआई और ऑनलाइन सुरक्षा से संबंधित जिम्मेदारी दी गई। इस दौरान उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऑनलाइन सुरक्षा, बौद्धिक संपदा, सेमीकंडक्टर, तकनीकी नवाचार तथा एआई सुरक्षा संस्थान जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्य किया। यही अनुभव



आगे चलकर उन्हें ब्रिटेन के पहले कैबिनेट स्तर के एआई मंत्री के रूप में स्थापित करने का आधार बना।

ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम ने सरकार के पुनर्गठन के दौरान एआई को अलग और अधिक महत्व देते हुए इस मंत्रालय को कैबिनेट स्तर का दर्जा दिया। इसके साथ ही कनिष्क नारायण को कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंत्री नियुक्त किया गया। यह निर्णय इस बात का संकेत है कि ब्रिटेन एआई को केवल तकनीकी विषय नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सार्वजनिक सेवाओं और वैश्विक प्रतिस्पर्धा से जुड़ा रणनीतिक क्षेत्र मानता है। इस नई व्यवस्था में एआई नीति का समन्वय सीधे सरकार के सर्वोच्च स्तर पर किया जाएगा।

आज पूरी दुनिया में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। चिकित्सा क्षेत्र में रोगों की शीघ्र पहचान, कृषि में बेहतर उत्पादन, शिक्षा में व्यक्तिगत शिक्षण, उद्योगों में स्वचालन, परिवहन में स्मार्ट सिस्टम और प्रशासन में डिजिटल सेवाओं के विस्तार के कारण एआई विकास का प्रमुख आधार बन चुका है। दूसरी ओर डीपफेक, साइबर अपराध, डेटा गोपनीयता, एथोर्सिटिक पक्षपात, गलत सूचना, कॉपीराइट विवाद और रोजगार पर संभावित प्रभाव जैसी चुनौतियां भी सामने हैं। इन परिस्थितियों में केवल तकनीक विकसित करना पर्याप्त नहीं है बल्कि उसके लिए संतुलित कानून और जिम्मेदार नीतियां भी आवश्यक हैं। हाल के अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों में भी नागरिकों ने एआई के विकास के साथ मजबूत सुरक्षा और

नियमन को प्राथमिकता देने की आवश्यकता जताई है।

कनिष्क नारायण की नई जिम्मेदारी का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यही है कि वे ऐसी नीतियां तैयार करें जो तकनीकी नवाचार को बाधित किए बिना सुरक्षा और नैतिकता सुनिश्चित करें। उन्हें यह संतुलन बनाना होगा कि उद्योगों को अनुसंधान और निवेश के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता मिले, लेकिन नागरिकों की गोपनीयता, डिजिटल अधिकार और सामाजिक हित भी सुरक्षित रहें। यह कार्य सरल नहीं है क्योंकि एआई तकनीक प्रतिदिन बदल रही है और उसके सामने आने वाली चुनौतियां भी लगातार विकसित हो रही हैं।

ब्रिटेन लंबे समय से स्वयं को एआई अनुसंधान और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है। वहां विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान और प्रौद्योगिकी कंपनियां सक्रिय हैं। सरकार चाहती है कि एआई आधारित स्टार्टअप, डेटा सेंटर और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधाओं का विस्तार हो, जिससे निवेश और रोजगार दोनों बढ़ें। कनिष्क नारायण की नियुक्ति इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है।

एआई मंत्री के रूप में उन्हें अंतरराष्ट्रीय सहयोग को भी मजबूत करना होगा। आज एआई की चुनौतियां किसी एक देश तक सीमित नहीं हैं। डीपफेक वीडियो, साइबर हमले, सीमा पार डेटा प्रवाह और वैश्विक डिजिटल कंपनियों के संचालन जैसे विषय अंतरराष्ट्रीय समन्वय

की मांग करते हैं। इसलिए ब्रिटेन को यूरोप, अमेरिका, भारत तथा अन्य देशों के साथ मिलकर साझा मानक और सहयोग तंत्र विकसित करने होंगे। ऐसे प्रयासों में कनिष्क नारायण की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

उनकी नियुक्ति का भारतीय दृष्टिकोण से भी विशेष महत्व है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय मूल के लोग विश्व के अनेक देशों में राजनीति, उद्योग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के शीर्ष पदों तक पहुंचे हैं। अब भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण तकनीक मानी जा रही कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में भी भारतीय मूल के व्यक्ति का नेतृत्व संभालना इस बात का प्रमाण है कि भारतीय प्रतिभा वैश्विक स्तर पर निरंतर अपनी पहचान बना रही है। यह उपलब्धि उन लाखों भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा है जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी और सार्वजनिक नीति के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर योगदान देना चाहते हैं।

हालांकि इस नियुक्ति के साथ अपेक्षाएं भी बहुत अधिक हैं। विशेषज्ञों का मानना ​​है कि केवल एआई मंत्रालय बना देने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। सरकार को स्पष्ट नियम, प्रभावी नियामक संस्थाएं, उद्योगों के साथ संवाद, अनुसंधान में निवेश और नागरिकों के हितों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। एआई का विकास तभी सफल माना जाएगा जब उसका लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे और उसके जोखिमों को न्यूनतम रखा जा सके।

भविष्य में एआई वैश्विक शक्ति संतुलन को भी प्रभावित करेगा। जिस प्रकार पिछली शताब्दी में औद्योगिक क्षमता और बाद में सूचना प्रौद्योगिकी ने देशों की आर्थिक स्थिति निर्धारित की, उसी प्रकार आने वाले वर्षों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता किसी भी राष्ट्र की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता का प्रमुख आधार बनेगी। ऐसे समय में ब्रिटेन द्वारा एआई को कैबिनेट स्तर पर प्राथमिकता देना यह दर्शाता है कि सरकार भविष्य की चुनौतियों और अवसरों को गंभीरता से देख रही है।

कनिष्क नारायण की नियुक्ति केवल एक व्यक्ति की सफलता नहीं बल्कि बदलती वैश्विक राजनीति, तकनीकी नेतृत्व और नीति निर्माण की नई दिशा का प्रतीक है। उनकी शिक्षा, प्रशासनिक अनुभव, तकनीकी समझ और राजनीतिक नेतृत्व उन्हें इस चुनौतीपूर्ण भूमिका के लिए उपयुक्त बनाते हैं। यदि वे नवाचार, सुरक्षा, नैतिकता और आर्थिक विकास के बीच संतुलित नीति तैयार करने में सफल रहते हैं, तो ब्रिटेन वैश्विक एआई शासन में अग्रणी भूमिका निभा सकता है। साथ ही यह नियुक्ति भारतीय मूल के लोगों की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा को भी नई ऊंचाई प्रदान करेगी। आने वाले वर्षों में उनकी कार्यशैली और नीतियां केवल ब्रिटेन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की एआई नीति और डिजिटल भविष्य पर प्रभाव डाल सकती हैं।

बुजुर्गों का सम्मान देश की स्वस्थ परंपरा बने,

सामाजिक संतुलन में बुजुर्गों की महिती भूमिका'



यह विडंबना है जब मनुष्य अत्यंत अनुभववी परिपक्व,प्रबुद्ध शालीन हो जाता है तब उसके अनुभव कार्य की लगनशीलता और परिपक्व मस्तिष्क का हम सदुपयोग नहीं करते उन्हें अवकाश प्रदान कर देते हैं। यह भी इस सिक्के का दूसरा पहलू है कि इस उम्र में शरीर में थकावट और वृद्धावस्था आ जाती है पर हम उन्हें सम्मान और यथा योग्य महत्त्व देकर उनके मार्गदर्शन और परामर्श का यथोचित लाभ लेकर अपने जीवन,व्यवसाय अथवा नई नीतियों में सफलता प्राप्त सकते हैं, पर अमूमन ऐसा होता नहीं है।

वृद्धावस्था को जीवन का अंतिम पड़ाव एवं समस्याओं से गिरी हुई अवस्था माना जाता है, क्योंकि इस अवस्था में वृद्धों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।म्रमय की रफ्तार के साथ समाज में अनेक परिवर्तन होने लगे हैं। नवीन पीढ़ी के लोग पुराने विचारों के लोगों का उनके जीवन में हस्तक्षेप उचित ना समझ कर बर्दाश्त नहीं करते हैं,इसी कारण युवा पीढ़ी बुजुर्गों एवं वृद्धों के विचारों की गहन उपेक्षा करने लगते हैं और बुजुर्गों को लगता है कि उनकी समाज में उपयोगिता धीरे धीरे कम हो रही है। जीवन का सांध्य काल आने पर मनुष्य कई समस्याओं से घिर जाता है। सबसे बड़ी समस्या शारीरिक क्षमता में कमी आ जाने की है, शरीर की सभी इंद्रियां धीमी पड़ जाती हैं,अनेक प्रकार की व्याधियों से शरीर घिर जाता है और मनुष्य धीरे-धीरे शरीर पर नियंत्रण खोता जाता है। उम्र के वृद्धावस्था के पड़ाव पर अनेक शारीरिक बीमारियों के साथ-साथ

अनुपयोगी, बोझ, फालतू समझा जाने लगता है, जिससे बुजुर्ग व्यक्ति के मन में एक प्रकार की वितुष्णा आने लगती है। और कई बुजुर्ग इस अवहेलना को ना बर्दाश्त कर आत्महत्या तक कर बैठते हैं। जो व्यक्ति कुछ समय पहले तक महत्वपूर्ण था, विशिष्ट था वह अचानक ही बोझ समझा जाने लगता है। उसके मान सम्मान एवं भावनाओं का महत्व बहुत कम हो जाता है। भागवैड़ वाली इस जिंदगी में युवा पीढ़ी अपने बुजुर्गों से एक दूरी बनाना शुरू कर देती है और वह व्यक्ति अकेला ही रह जाता है। जब मनुष्य अपने को एकाकी समझने बनेन लगती है। लोगों के संपर्क में न रहना, सहयोगी तथा मित्रों की मृत्यु भी मानसिक तनाव का बड़ा कारण होती है। आत्मविश्वास की धीरे-धीरे कमी होने लगती है, जिससे मानसिक विकृति अकेलापन आदि जैसे रोगों का निर्माण होने लगता है। इस अवस्था में मान सम्मान की कमी की समस्या तो होती ही है, दूसरी तरफ सीमित तथा अल्प धन की उपलब्धता के कारण आर्थिक कष्ट भी वृद्धों को उठाना पड़ता है। इसके साथ ही परिवार तथा समाज की नजरों में व्यक्ति

अपने मां-बाप से अलग होकर रहने की चाहत हमारे देश में एक गंभीर समस्या पैदा करती है। वृद्ध व्यक्ति या दंपति को जिस आयु में पुत्र, पुत्रियों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, ऐसे समय में पुत्र द्वारा उनकी देखभाल छोड़कर अलग रहने के लिए अलग मकान बनाना या किराए पर रहना, उस दंपति या व्यक्ति को मानसिक रूप से प्रताड़ित भी करती है। भारत देश वही देश है यहां की संस्कृति में परिवार के बुजुर्ग को भगवान के समान माना जाता था, किंतु संयुक्त परिवार प्रणाली के विघटन के कारण आज की नई युवा पीढ़ी ना तो बड़ों के अनुशासन में रहना चाहती है नहीं उन्हें किसी प्रकार का आदर सम्मान देना चाहती है। औद्योगिकरण और विसंस्कृतिकरण प्रणाली के फल स्वरूप युवा पीढ़ी के रहन-सहन एवं जीवन शैली में तीव्र बदलाव देखा जा रहा है। इस युग में व्यक्ति जितना अपने कार्यों में व्यस्त हो गया है कि उसको परिवार के साथ बैठने, रहने की फुर्सत ही नहीं मिल पाती। भारत में बदलते परिवेश में ओल्ड एज होम की अवधारणा तेजी से बल पकड़ती जा रही है। नई पीढ़ी तरह पुरानी

संवाद की डोर, क्रोध की मशाल...!

फिर सड़कों पर "शोर" उठा, फिर मन में सवाल जगे, लोकतंत्र की चौखट पे क्यों ऐसे बवंडर दिखने लगे? राजधानी की धड़कन ने फिर से आह भरी चुपचाप, आँसू, धक्का, भीड़, विवशता सभी ने ओढ़ा नकाब।

जब संवाद की डोर टूटे, क्रोध मशाल बनके आता है, सत्य कहीं कोनों में सिमटकर, झूठ उछलता जाता है। कुर्सी हो या फिर आंदोलन, दोनों की है एक कसौटी, जनहित सबसे ऊपर हो, ना हो सिर्फ सत्ता की रोटी।

यहाँ पत्थर से "समाधान" नहीं, लाठी से विश्वास नहीं, चाव किसी के ही लेकिन, उनसे कोई "विकास" नहीं। दिल्ली केवल "शहर" नहीं, भारत की बड़ी पहचान है, इसकी हर एक पीड़ा में छिपी "लोकतंत्र" की जान है।

आओ ऐसा पथ चुनें जहाँ मतभेद रहें, "मनभेद" नहीं, पुनः संवादों की ज्योति जले, हिंसा का फिर भेद नहीं। जन की आशा कहती है, सब मिलकर ये प्रण कर लें, लोकतंत्र की गरिमा खातिर प्रेम, विवेक का दीप जले।

संजय एम तराणेकर (कवि, लेखक व समीक्षक) इन्दौर-452011 (मध्य प्रदेश) मो. 98260 25986(स्व-रचित, मौलिक व अप्रकाशित)

स्वामी मुद्रक एवं प्रकाशक रमन कुमार झा द्वारा साईं प्रिटिंग प्रेस बी-42 सेक्टर 07 नोएडा से मुद्रित कराकर नियर दुर्गा पब्लिक स्कूल श्याम लाल कॉलोनी बरौला सेक्टर 49 नोएडा 201304, गौतमबुद्धनगर उत्तर प्रदेश से प्रकाशित।

संपर्क 9891706853, संपादक- रमन कुमार झा, समस्त विवादों का निपटारा गौतमबुद्धनगर न्यायालय मे होगा। Website: https://samajjagran.in/ Email: vatankiawaz@gmail.com UPHIN/2021/84200

हाईराइज सोसायटियों में घर के पास बनेंगे मतदान केंद्र जिला निर्वाचन अधिकारी ने आरडब्ल्यूए-एओए पदाधिकारियों के साथ की बैठक, दो दिन में मांगे सुझाव

समाज जागरण/संदीप गर्ग गौतमबुद्धनगर। जिले की बहुमंजिली आवासीय सोसायटियों और सेक्टरों में रहने वाले मतदाताओं को उनके घर के निकट मतदान केंद्र उपलब्ध कराने की दिशा में जिला प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। इसी क्रम में बुधवार को जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आरडब्ल्यूए एवं एओए के अध्यक्षों, सचिवों और अन्य पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार 1200 मतदाताओं के मानक के आधार पर वर्तमान मतदेय स्थलों का पुनर्गठन तथा आवश्यकता के अनुसार नए मतदान केंद्रों का चिन्हांकन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य मतदाताओं को उनके निवास के निकट, सुगम एवं सुविधाजनक मतदान केंद्र



उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि जिन हाईराइज सोसायटियों और सेक्टरों में 300 से 1200 मतदाता निवास करते हैं तथा जहां सुरक्षित वातावरण के साथ आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहां नए मतदेय स्थल स्थापित करने के संबंध में सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने आरडब्ल्यूए एवं एओए

पदाधिकारियों से अपील की कि यदि उनके पास इस संबंध में कोई व्यवहारिक एवं जनहितकारी सुझाव या प्रत्यावेदन हो तो उसे अगले दो दिनों के भीतर जिला निर्वाचन कार्यालय अथवा ई-मेल adeo-gbn@nic.in पर उपलब्ध कराएं, ताकि नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा सके। उन्होंने श्रमिक बहुल क्षेत्रों में रहने वाले मतदाताओं की सुविधा पर भी

विशेष जोर देते हुए कहा कि ऐसे क्षेत्रों के लिए भी उपयुक्त मतदान केंद्रों के संबंध में सुझाव दिए जाएं, जिससे प्रत्येक मतदाता को निकटतम मतदान केंद्र की सुविधा मिल सके। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदेय स्थलों के निर्धारण, 1200 मतदाताओं के मानक तथा भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी भालचंद्र त्रिपाठी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी अजीत कुमार सिंह, प्रभारी सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम सदर (न्यायिक) अरुण कुमार, तहसीलदार जेवर प्रतीक चौहान, ईओ दायरी शालिनी गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं आरडब्ल्यूए-एओए के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

पोषण योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, पात्र लाभार्थियों तक समय पर पहुंचे पुष्टाहार : जिलाधिकारी

जिला पोषण समिति की बैठक में योजनाओं की समीक्षा, मातृ एवं शिशु पोषण पर विशेष फोकस के निर्देश

समाज जागरण/संदीप गर्ग गौतमबुद्धनगर। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला पोषण समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की विभिन्न योजनाओं, पोषण ट्रैकर, संभव अभियान-6.0, सक्षम आंगनवाड़ी 2.0, कुपोषण प्रबंधन तथा आंगनवाड़ी केंद्रों की आधारभूत सुविधाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि संभव अभियान-6.0 के तहत जुलाई माह में मातृत्व पोषण तथा अगस्त में जन्म से छह माह तक के शिशुओं के पोषण पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र गर्भवती महिलाओं का समय पर पंजीकरण सुनिश्चित करने तथा आशा और एएनएम के समन्वय से ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस का शत-प्रतिशत आयोजन कराने के निर्देश दिए। बैठक में तीन से छह वर्ष तक के बच्चों की अपार (अडअफ) आईडी बनाने तथा ई-कवच ऐप पर अति कुपोषित बच्चों की प्रविष्टि समयबद्ध रूप से पूर्ण कराने के भी निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि पुष्टाहार वितरण में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए और सभी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

मदिय दुकानों का औचक निरीक्षण, सीसीटीवी और पीओएस मशीन से शत-प्रतिशत बिक्री के निर्देश

आबकारी विभाग का विशेष अभियान, स्टॉक का किया सत्यापन

समाज जागरण/संदीप गर्ग गौतमबुद्धनगर। आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश के निर्देश पर जिलाधिकारी एवं पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में आबकारी विभाग ने जिले में विशेष अभियान चलाकर विभिन्न मदिरा दुकानों का औचक निरीक्षण किया। जिला आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में 21 जुलाई 2026 को संचालित अभियान के दौरान जनपद की कम्पोजिट शॉप, मॉडल शॉप और प्रीमियम रिटेल शॉप का निर-िक्षण कर मदिरा के स्टॉक का सत्यापन किया गया। निरीक्षण के दौरान अनुज्ञापियों एवं विक्रेताओं को निर्देश दिए गए कि सीसीटीवी कैमरे इस प्रकार लगाए



जाएं कि दुकान पर आने वाले ग्राहकों और बिक्री काउंटर पर होने वाली गतिविधियों की स्पष्ट रिकॉर्डिंग हो सके। साथ ही सभी मदिरा दुकानों पर पीओएस मशीन के माध्यम से शत-प्रतिशत बिक्री सुनिश्चित करने

के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए। आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया कि अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित अनुज्ञापियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

अपने व्यापार का करें प्रचार प्रसार
दैनिक समाज जागरण मे खबर और विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें।
न्यूज पोर्टल पर चलवाये मात्र 200 रुपये रोज मे।

भाजपा का बूथ अध्यक्ष सम्मेलन संपन्न, संगठन सशक्त बनाने का आह्वान महेश चौहान बोले- नोएडा का हर बूथ बने भाजपा का सबसे मजबूत संगठनात्मक केन्द्र

समाज जागरण/संदीप गर्ग नोएडा। भारतीय जनता पार्टी नोएडा महानगर की ओर से बुधवार को सेक्टर-91 स्थित पंचशील बालक इंटर कॉलेज में महानगर अध्यक्ष महेश चौहान के नेतृत्व में भव्य बूथ अध्यक्ष सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में संगठन की आगामी कार्ययोजना, बूथ सशक्तिकरण एवं संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व महापौर आशु वर्मा तथा विशिष्ट अतिथि पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं गौतमबुद्धनगर सांसद डॉ. महेश शर्मा रहे। सम्मेलन में बड़ी संख्या में बूथ अध्यक्षों, मंडल पदाधिकारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

‘बूथ जीता तो चुनाव जीता’ मुख्य अतिथि आशु वर्मा ने कहा कि भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसके बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कहा कि "बूथ जीता तो चुनाव जीता" केवल नारा नहीं, बल्कि संगठन की कार्यशैली का आधार है। उन्होंने सभी बूथ अध्यक्षों से मतदाताओं से निरंतर संपर्क बनाए



रखने और केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया।

उन्होंने संगठन के वार्षिक कार्यक्रमों को प्रत्येक बूथ पर प्रभावी ढंग से आयोजित करने की भी अपील की।

बूथ अध्यक्ष संगठन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी : डॉ. महेश शर्मा

सांसद डॉ. महेश शर्मा ने कहा कि भाजपा आज विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन इसलिए है क्योंकि उसका बूथ स्तर तक मजबूत

नेटवर्क है। उन्होंने कहा कि बूथ अध्यक्ष संगठन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं और उन्हें नए मतदाताओं, लाभार्थियों एवं आम जनता से लगातार संवाद बनाए रखना चाहिए।

उन्होंने कार्यकर्ताओं से केंद्र एवं उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को घर-घर तक पहुंचाने और सेवा, अनुशासन व संगठन की भावना के साथ कार्य करने का आह्वान किया।

हर बूथ को मजबूत बनाने का लक्ष्य

सम्मेलन के समापन पर महानगर

जूनियर बालक फुटबॉल टीम चयन ट्रायल 24 जुलाई को

प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का होगा चयन, आधार कार्ड व जन्मतिथि प्रमाण-पत्र लाना अनिवार्य

समाज जागरण/संदीप गर्ग गौतमबुद्धनगर। प्रदेश स्तरीय समन्वय जूनियर बालक फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए जनपद गौतमबुद्धनगर की टीम के चयन हेतु 24 जुलाई को जिला स्तरीय चयन-ट्रायल आयोजित किए जाएंगे। चयनित खिलाड़ी 25 जुलाई को मेरठ में होने वाले मंडलीय ट्रायल्स में हिस्सा लेंगे। प्रभारी क्रीड़ा अधिकारी डॉ. परवेज अली ने बताया कि खेल निदेशालय

उत्तर प्रदेश एवं क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी, मेरठ मंडल के निर्देशानुसार यह चयन प्रक्रिया आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता में वही खिलाड़ी भाग ले सकेंगे जिनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 2011 से 31 दिसंबर 2012 के बीच हो।

जिला स्तरीय चयन-ट्रायल 24 जुलाई को अपराह्न 3 बजे एस्टर पब्लिक स्कूल, डेल्टा-2, ग्रेटर

नोएडा में आयोजित होंगे। चयनित खिलाड़ियों के लिए 25 जुलाई को प्रातः 10 बजे कैलाश प्रकाश स्टे-डियम, मेरठ में मंडलीय ट्रायल्स होंगे। इसके बाद प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता 1 से 8 अगस्त 2026 तक डॉ. भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम, मऊ में आयोजित की जाएगी।

डॉ. परवेज अली ने बताया कि

नोएडा में 2.48 करोड़ रुपये की अवैध दवाएं बरामद सेक्टर-76 स्थित फ्लैट पर संयुक्त छापेमारी, एक आरोपी गिरफ्तार

समाज जागरण/संदीप गर्ग गौतमबुद्धनगर। नोएडा के सेक्टर-76 स्थित एक फ्लैट में अवैध रूप से संग्रहित लगभग 2.48 करोड़ रुपये मूल्य की दवाएं बरामद की गई हैं। संयुक्त छापेमारी के दौरान एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मामले में आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। औषधि निरीक्षक जयसिंह ने बताया कि अंतरराज्यीय प्रकोष्ठ, अपराध शाखा, चाणक्यपुरी (नई दिल्ली) से प्राप्त सूचना एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर सीडीएससीओ उत्तर जोन, गाजियाबाद, अपराध शाखा, नई दिल्ली तथा औषधि विभाग गौतमबुद्धनगर की संयुक्त टीम ने अमरापल्ली प्रिंसली एस्टेट, सेक्टर-76 स्थित फ्लैट संख्या जे-402 पर



छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान फ्लैट में आनंद कुमार, बसंत लाल वर्णवाल एवं प्रीति मौजूद मिले। जांच में पता चला कि फ्लैट का उपयोग बड़ी मात्रा में तैयार औषधियों के अवैध भंडारण के लिए किया जा रहा था। मौके से

गोलियां, कैप्सूल, इंजेक्शन, टीके, ह्यूमन एल्ब्यूमिन, इम्यूनोग्लोबुलिन, रेबीज वैक्सीन, सर्पदंश एंटीसीरम सहित कई महंगी एवं जीवनरक्षक जैविक दवाएं बरामद की गईं। जांच में कई दवाओं पर "सरकारी आपूर्ति, बिक्री के लिए नहीं" अंकित

महिला आयोग की सदस्य डॉ. मीनाक्षी भराला ने सुनी महिलाओं की फरियाद

19 मामलों की जनसुनवाई, 8 शिकायतों का मौके पर निस्तारण; अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश

समाज जागरण/संदीप गर्ग गौतमबुद्धनगर। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉ. मीनाक्षी भराला की अध्यक्षता में बुधवार को विकास भवन सभागार में महिला जनसुनवाई का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आई महिलाओं ने अपनी शिकायतें आयोग के समक्ष रखीं। जनसुनवाई के दौरान पुलिस विभाग से संबंधित 19 प्रकरणों की सुनवाई की गई, जिनमें 8 मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया।

डॉ. मीनाक्षी भराला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शेष मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि महिलाओं से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण अपनाने हुए पीड़ितों को



शीघ्र न्याय दिलाना सभी संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है।

उन्होंने पुलिस, महिला कल्याण विभाग तथा अन्य अधिकारियों को निर्देशित किया कि महिला फरियादियों के साथ सम्मानजनक एवं सहयोगपूर्ण व्यवहार किया जाए तथा उनकी समस्याओं का निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने कहा कि राज्य महिला आयोग महिलाओं को न्याय दिलाने के साथ-साथ उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का भी कार्य कर रहा है।

'शक्ति संवाद' में छात्राओं को किया जागरूक

जनसुनवाई के बाद डॉ. मीनाक्षी

सेक्टर-19 में नालियों पर अतिक्रमण हटाने के निर्देश, दो दिन की मोहलत

अतिक्रमण नहीं हटाने पर बारिश में जलभराव की जिम्मेदारी भवन स्वामियों की होगी : नोएडा प्राधिकरण

समाज जागरण/संदीप गर्ग नोएडा। नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर-19 के ए. बी और सी ब्लॉक में नालियों एवं सड़क की पटरी पर किए गए अतिक्रमण को लेकर सख्त रुख अपनाया है। प्राधिकरण ने संबंधित भवन स्वामियों को दो दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं।

प्राधिकरण के अनुसार, 18 जुलाई 2026 को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (वी.टी.) द्वारा वर्क सर्किल-2 क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि सेक्टर-19 के अधिकांश भवन



स्वामियों ने नालियों और सड़क की पटरी पर अतिक्रमण कर रखा है।

इससे नालियों की नियमित सफाई प्रभावित हो रही है और बरसात के

मोबाइल स्नैचिंग गैंग का पदार्पण, 25 लूटे गए मोबाइल के साथ दो गिरफ्तार

नॉलेज पार्क पुलिस की कार्रवाई, फर्जी नंबर प्लेट लगी अपाचे बाइक और अवैध हथियार भी बरामद

समाज जागरण/संदीप गर्ग ग्रेटर नोएडा। थाना नॉलेज पार्क पुलिस ने मोबाइल फोन स्नैचिंग करने वाले दो शांति बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 25 छिने गए मोबाइल फोन, फर्जी नंबर प्लेट लगी एक अपाचे मोटरसाइकिल तथा दो अवैध तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं।

पुलिस के अनुसार, 22 जुलाई 2026 को ग्राम गुर्जरपुर रेलवे अंडरपास के पास से फैजान पटान और फरमान को गिरफ्तार किया गया। फैजान पटान रबूपुरा क्षेत्र का



निवासी है, जबकि फरमान मूल रूप से बुलंदशहर का रहने वाला है। दोनों के आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है।

हत्या के प्रयास के मामले में चार वांछित आरोपी गिरफ्तार जेवर पुलिस ने दो अवैध तमंचे, कारतूस और खोखे किए बरामद

समाज जागरण/संदीप गर्ग गौतमबुद्धनगर। थाना जेवर पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में वांछित चार आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से दो अवैध तमंचे, दो जिंदा कारतूस और दो खोखे कारतूस बरामद किए हैं।

पुलिस के अनुसार, 22 जुलाई 2026 को छतंगा तिराहे से झमन, भोला उर्फ दिनेश, विजय उर्फ बिज्जो और

विक्रम को गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान झमन और भोला उर्फ दिनेश के कब्जे से एक-एक अवैध तमंचा (.315 बोर), एक-एक जिंदा कारतूस और एक-एक खोख़ा कारतूस बरामद हुआ।

20 जुलाई को हुई थी फायरिंग पुलिस के मुताबिक, 20 जुलाई 2026 को वादी ने थाना जेवर में

राहगीरों को बनाने थे निशाना पृष्ठताछ में सामने आया कि आरोपी नॉलेज पार्क और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में रह चलते लोगों से मोबाइल फोन

न अपने साथियों के साथ मिलकर गाली-गलौज की और जान से मारने की नीयत से उसके पुत्र पर अवैध तमंचे से फायरिंग कर दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।

ट्रायल में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को आधार कार्ड तथा सत्यापित जन्मतिथि प्रमाण-पत्र की छायाप्रति साथ लाना अनिवार्य होगा। जन्मतिथि प्रमाण-पत्र पर तिथि अंक एवं शब्द दोनों में स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिए। निर्धारित आयु एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत न करने वाले खिलाड़ियों को चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा।

मिला। इसके अलावा, जिन दवाओं को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सुरक्षित रखा जाना चाहिए था, उन्हें सामान्य कमरे के तापमान पर रखा गया था, जिससे उनके दुरुपयोग और गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका जताई गई।

छापेमारी में जब्त दवाओं का कुल मूल्य 2,48,66,658.31 रुपये आंका गया है। जांच के लिए आठ दवा उत्पादों के नमूने एकत्र किए गए हैं, जबकि आनातित दवाओं के नमूने सीडीएससीओ द्वारा अलग से लिए जाएंगे। कार्रवाई के दौरान आनंद कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया तथा जब्त दवाओं और अन्य सामग्री को कब्जे में लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

भराला ने महामाया बालिका इंटर कॉलेज, सेक्टर-44, नोएडा में आयोजित 'शक्ति संवाद' कार्यक्रम में छात्राओं से संवाद किया। उन्होंने छात्राओं को महिला सुरक्षा, शिक्षा, आत्मनिर्भरता और सैवधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने तथा अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया।

कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी भालचंद्र त्रिपाठी, डीसीपी महिला सुरक्षा सुनीति, परियोजना निदेशक डीआरडीए नेहा सिंह, जिला प्रोबेशन अधिका-री मनोज कुमार पुष्कर, जिला विद्यालय निरीक्षक चंद्रशेखर, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी आशीष कुमार सिंह, एडीसी जितेंद्र मौर्व्य सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

